

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 503]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 18 सितम्बर 2017—भाद्र 27, शक 1939

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 18 सितम्बर 2017

क्र. एफ-ए-3-63-2017-1-पांच (104).—राज्य सरकार मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 18 सितम्बर, 2017 को उस तारीख के रूप से नियत करती हैं जिसको उक्त अधिनियम की धारा 51 की उपधारा (1) के उपबंध, उक्त अधिनियम की धारा 51 की उपधारा (1) के खण्ड (क) और खण्ड (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट व्यक्तियों और उक्त अधिनियम की धारा 51 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन नीचे विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के संबंध में प्रवृत्त होंगे, अर्थात्:—

(क) किसी कार्य को करने के लिये साम्या या नियंत्रण द्वारा पचास प्रतिशत या अधिक की भागीदारी के साथ,—

(i) संसद या किसी राज्य विधान मंडल के अधिनियम द्वारा गठित ; या

(ii) किसी सरकार द्वारा स्थापित,

कोई प्राधिकरण या बोर्ड या कोई अन्य निकाय ;

(ख) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित कोई सोसाइटी ;

(ग) पब्लिक सेक्टर उपक्रम :

परन्तु उक्त व्यक्ति, राज्य सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर, बाद में अधिसूचित की जाने वाली तारीख से, कराधेय माल या सेवाओं या दोनों के प्रदायकर्ता को किए गए या जमा किए संदाय से कर की कटौती करने का दायी होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण परमार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 18 सितम्बर 2017

क्र. एफ-ए-3-63-2017-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ-ए-3-63-2017-1-पांच (104), दिनांक 18 सितम्बर 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण परमार, उपसचिव.

Bhopal, the 18th September 2017

No. F-A-3-63-2017-1-V-(104).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (No.19 of 2017), the State Government hereby appoints the 18th day of September, 2017 as the date on which the provisions of sub-section (1) of Section 51 of the said Act shall come into force with respect to persons specified under clauses (a) and (b) of sub-section (1) of Section 51 of the said Act and the persons specified below under clause (d) of sub-section (1) of Section 51 of the said Act, namely:—

(a) an authority or a board or any other body,—

- (i) set up an Act of Parliament or a State Legislature; or
- (ii) established by any Government,

with fifty-one percent or more participation by way of equity or control, to carry out any function;

(b) society established by the Central Government of the State Government or a Local Authority under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860);

(c) public sector undertakings:

Provided that the said persons shall be liable to deduct tax from the payment made or credited to the supplier of taxable goods or services or both with effect from a date to be notified subsequently, on the recommendations of the Council, by the State Government.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ARUN PARMAR, Dy. Secy.